



गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

PRGI No. GJHIN/26/A1393

वर्ष : 01

अंक : 001

दि. 01.10.2026,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

कांग्रेस में लौटेंगे ‘बापू’? शंकरसिंह वाघेला के बदले सुरों से गुजरात की सियासत में हलचल, हाईकमान से बातचीत जारी

गांधीनगर। गुजरात की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला एक बार फिर राजनीतिक सुखियों में हैं। करीब नौ साल पहले कांग्रेस से अलग होने वाले वाघेला ने अब दोबारा पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई है। उनके इस रुख के बाद गुजरात की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खास बात यह है कि कुछ ही सप्ताह पहले तब वाघेला अपनी अलग राजनीतिक राह पर आगे बढ़ने और वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ने की बात कह रहे थे। अब उनके कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ने की संभावित कोशिश ने राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलों को तेज कर दिया है। वाघेला की कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी बातचीत चलने की पुष्टि की है। चावड़ा के मुताबिक वाघेला और उनके समर्थकों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और इस संबंध में पार्टी के हाईकमान के साथ चर्चा जारी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस में उनके औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी में उनकी संभावित भूमिका और जिम्मेदारी को लेकर भी नेतृत्व स्तर पर

विचार किया जाना बाकी है। यानी फिलहाल मामला बातचीत के स्तर पर है और अंतिम फैसला होना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि वाघेला का राजनीतिक रुख पिछले कुछ समय में कई बार बदला है। सितंबर की शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस में लौटने का समय निकल चुका है और उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से सक्रिय करने और 2 अक्टूबर से राजनीतिक अभियान शुरू करने की योजना भी बनाई थी। उस समय उनके तेवर अलग राजनीतिक मंच खड़ा करने के थे। लेकिन अब कांग्रेस के साथ वाघेला की खबरों ने उनके अगले कदम को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। वाघेला ने स्वयं भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत की पुष्टि की है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यदि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए व्यापक राजनीतिक प्रयास होता है तो वे कांग्रेस के साथ आने की तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और



पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी से बातचीत होने की बात कही है। हालांकि उनकी वापसी को अंतिम रूप देने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाघेला का राजनीतिक सफर गुजरात की राजनीति के कई महत्वपूर्ण दौर का साक्षी रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनीतिक संगठन में सक्रियता के साथ की। 1977 में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसके बाद गुजरात की राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ता गया।

भाजपा में रहते हुए वे राज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और बाद में पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के कारण अलग राजनीतिक राह पर चले गए। वर्ष 1995 में भाजपा से अलग होने के बाद वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल और गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाई। हालांकि उस चुनाव में उनके राजनीतिक मंच का कोई उम्मीदवार विधानसभा तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद भी वाघेला ने सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं बनाई। वर्ष 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रुख किया और कुछ समय तक पार्टी में

जुड़ाव हुआ। कांग्रेस में रहते हुए वाघेला ने राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा रहे और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। गुजरात की राजनीति में उनकी अपनी पहचान और समर्थकों का आधार बना रहा। लंबे समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने के कारण वे गुजरात के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका राजनीतिक नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली। उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी अलग हुए। इसके बाद उन्होंने जन विकल्प मोर्चा बनाया और गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाई। हालांकि उस चुनाव में उनके राजनीतिक मंच का कोई उम्मीदवार विधानसभा तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद भी वाघेला ने सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं बनाई। वर्ष 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रुख किया और कुछ समय तक पार्टी में

राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाली। बाद में उन्होंने एनसीपी छोड़ दी। इसके बाद कुछ समय तक अलग-अलग राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहने के बाद उन्होंने नवंबर 2024 में प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की शुरुआत की। वर्ष 2026 में उन्होंने इस राजनीतिक मंच को फिर सक्रिय किया और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करने का संकेत दिया। सितंबर 2026 में वाघेला ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी। उस समय उनका कहना था कि वे अपनी पार्टी के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधीनगर में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की योजना भी बताई थी। इसी कार्यक्रम और उनके नए राजनीतिक रुख के बीच अब कांग्रेस से बातचीत की खबर सामने आई है। गुजरात कांग्रेस के लिए भी वाघेला की संभावित वापसी का मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित चावड़ा ने कहा है कि पार्टी ऐसे नेताओं और समूहों को एक साझा राजनीतिक मंच देने की कोशिश कर रही है, जो भाजपा से अलगूट है। उन्होंने वाघेला के भाजपा,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का भी उल्लेख किया। ये चावड़ा के राजनीतिक आकलन और बयान हैं; कांग्रेस की रणनीति को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व के स्तर पर होना बाकी है। वाघेला की वापसी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा है। कुछ रिपोर्टों में पार्टी के अंदर उनके पुराने राजनीतिक फैसलों को लेकर मतभेद और सावधानी का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2017 में उनके कांग्रेस छोड़ने और उनके साथ कई विधायकों के अलग होने की घटना आज भी पार्टी की राजनीतिक स्मृति के हिस्सा है। इसलिए संभावित वापसी केवल सदस्यता का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी चर्चा का विषय है कि यदि वे कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें किस भूमिका में रखा जाएगा और पार्टी के चुनावी संगठन में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। वाघेला की उम्र 86 वर्ष है और वे गुजरात की राजनीति के सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में भाजपा, कांग्रेस, अलग क्षेत्रीय राजनीतिक मंच और एनसीपी जैसे अलग-अलग पड़ाव रहे हैं। यही वजह

है कि उनके किसी भी राजनीतिक फैसले पर गुजरात में विशेष नजर रहती है। अब एक बार फिर उनके कांग्रेस से संभावित जुड़ाव की खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक दलों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल उनकी भूमिका को लेकर होगा। यदि कांग्रेस में वापसी पर सहमति बनती है तो पार्टी नेतृत्व को यह तय करना होगा कि वाघेला की वरिष्ठता, अनुभव और गुजरात में उनके पुराने राजनीतिक संपर्कों का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। दूसरी ओर वाघेला के लिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा कि वे अपनी अलग पार्टी और राजनीतिक मंच को जारी रखते हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर आगे की राजनीतिक राह तय करते हैं। गांधीनगर नगर निगम चुनाव भी नजदीक हैं और इसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव आगे की राजनीतिक राह तय करते हैं। 2027 की तैयारी और तेज होगी। ऐसे में राज्य की राजनीति में पुराने नेताओं की सक्रियता, नए राजनीतिक गठजोड़ और अलग-अलग दलों के बीच संभावित आवाजाही पर नजर बनी रहेगी। वाघेला की संभावित कांग्रेस वापसी इसी व्यापक राजनीतिक गतिविधि के बीच सामने आई है।

पटाखों पर पूरी पाबंदी नहीं, लेकिन 24 घंटे भी नहीं मिलेगी छूट ; सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संतुलन पर दिया जोर

नई दिल्ली। दिवाली और अन्य त्योहारों से पहले पटाखों के इस्तेमाल को रोकने चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने संकेत दिया कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को स्वीकार करना उसके लिए उचित नहीं होगा, लेकिन साथ ही पटाखों के बेरोकटोक इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। अदालत ने धार्मिक भावनाओं और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर प्रदूषण के असर को लेकर अदालत ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि उसका रूख न तो पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने का है और न ही उन्हें पूरे दिन इस्तेमाल करने की अनुमति देने का। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह है कि त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल की धार्मिक और सामाजिक परंपरा को किस तरह बनाए रखते हुए उससे होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को सीमित किया जाए। इसके लिए प्रदूषण चलाने के निर्धारित समय और इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखों के प्रकार को लेकर नियम तय करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। यह मामला न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मंरीर की पीठ के समक्ष चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकाधिक वाद सूची में दोनों न्यायाधीशों की पीठ की 30 सितंबर 2026 की कार्यवाही दर्ज है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी समाधान में दोनों पक्षों को ध्यान में रखना



होगा। एक तरफ त्योहारों के साथ लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ पटाखों से निकलने वाले धुंरे और शोर का असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के अलावा ऐसे लोग भी प्रदूषण से प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें पहले से सांस या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसलिए अदालत, ऐसा संतुलित रास्ता तलाशना चाहती है, जिसमें पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति तो हो, लेकिन उसके लिए स्पष्ट सीमाएं भी तय हों। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पटाखों के संबंध में तकनीकी प्रस्ताव भी अदालत के सामने रखा गया। सरकार ने कुछ निर्धारित शतों के साथ नई पीढ़ी के लड़ी वाले पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने की दिशा में सुझाव पेश किया। इन पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल से जुड़े तकनीकी मानकों पर पर्यावरण विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया गया है। लड़ी वाले पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिनमें कई छोटे पटाखों के एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है और जलाए जाने के बाद वे क्रमशः फटते हैं। इनके कारण एक साथ बड़ी मात्रा में शोर, धुआं और टोस करवा उड़सना हो सकता है। इसी वजह से पटाखों को लेकर पहले भी

अदालत में इन पर विशेष रूप से चर्चा होती रही है। हालांकि उनकी वापसी को और से अब ऐसे पटाखों के लिए संख्या, आकार और धमकों के बीच अंतराल जैसे तकनीकी मानक तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षकारों और तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की है। लड़ी वाले पटाखों के विनिर्देशों को लेकर सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर-नरी से भी सुझाव लिए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में पटाखों की संख्या, उनके शेल का आकार और लगातार होने वाले धमकों के बीच समय अंतराल जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। त्योहारों के दौरान जब बड़ी संख्या में पटाखे एक साथ जलाए जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि केवल समय निर्धारित कर देने से समस्या का समाधान

नहीं होगा, क्योंकि पहले भी पटाखे चलाने की समय-सीमा से जुड़े निर्देशों का पालन पूरी तरह नहीं हो पाया है। उनका तर्क था कि दिवाली के आसपास पहले से मौजूद अन्य प्रदूषण स्रोतों के साथ पटाखों का धुआं वायु गुणवत्ता को और प्रभावित कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदूषण के स्तर को केवल पटाखों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस अवधि में पराली जलाने सहित अन्य स्रोत भी कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में दो दिनों में बड़ी मात्रा में पटाखे जलाने का प्रभाव गंभीर हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने पटाखों पर सख्त पाबंदी की मांग की। अदालत ने हालांकि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की दिशा में जाने के बजाय व्यवहारिक और संतुलित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत का संकेत है कि पटाखों के लिए समय की सीमा तय करना और उनके प्रकार पर नियंत्रण रखना एक संभावित रास्ता हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नियमों का पालन महत्वपूर्ण रहेगा और निर्धारित सीमा से बाहर पटाखे चलाने की अनुमति स्वतः नहीं मानी जाएगी। सुनवाई में ग्रीन पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल का मुद्दा भी सामने आया। केंद्र सरकार ने जनरेशन-2 ग्रीन पटाखों में बेरियम के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए आइटडीए प्रक्षेपण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। सरकार की ओर से बताया गया कि सीएसआईआर-नरी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलग-अलग वायु गुणवत्ता परिसरितियों में परीक्षण के लिए चार शहरों का सुझाव दिया है।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। आरोप तय होने के साथ ही मामला अब मुकदमे की अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ गया है। अदालत ने सभी पक्षों को आरोप की प्रति उपलब्ध करने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय तय किया है और मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। यह मामला रांची के बड़गाई अंचल में स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण, कब्जे और हस्तांतरण से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है। इंडी की जांच में जमीन से जुड़े दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और कथित लेन-देन की पड़ताल की गई। एजेंसी के आरोप हैं कि उक्त जमीन को अवैध तरीके से हासिल करने और कब्जे में रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर फर्जी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का सहारा लिया गया। अदालत में आरोप तय होने से पहले हेमंत सोरेन की ओर से कार्यवाही को रोकने और आरोप तय करने की प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत में उनके खिलाफ फैला रही आरोप तय करने की प्रक्रिया की वजह पर सवाल उठाया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस स्तर पर



विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में इस मामले से जुड़े उन दस्तावेजों को देखने के लिए समय मांगा गया था, जिन पर अधिग्रहण पक्ष ने भरोसा नहीं किया है। 24 सितंबर को हुई सुनवाई में उनके वकील संजीव सहाय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच और पुष्टि के लिए बचाव पक्ष को समय चाहिए। इसके बाद विशेष अदालत ने आरोप तय करने की अगली तारीख 30 सितंबर निर्धारित की थी। अदालत ने सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले विशेष अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकने की सोरेन की मांग स्वीकार नहीं की थी। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में आगे की जांच के लिए अतिरिक्त शिकायत दाखिल

के तहत पूरक जांच की संभावना अपने आप में मौजूदा शिकायत के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही रोकने का आधार नहीं बनती। विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। मामले की पुष्टीभूमि जमीन के कथित फर्जी अधिग्रहण से जुड़ी जांच से सामने आई। झारखंड हाईकोर्ट के 18 सितंबर के आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार, इंडी की जांच के दौरान रांची में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की जानकारी सामने आई थी। जांच एजेंसी ने बड़गाई क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़े और जमीन के दस्तावेजों से संबंधित कई अनियमितताओं की जांच की। हाईकोर्ट के आदेश में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख था। इंडी की ओर से लगाए गए आरोपों में जमीन पर कथित कब्जे और उससे जुड़े लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर कुछ ऐसे जांच के लिए अतिरिक्त शिकायत दाखिल

शामिल किया है, जिनमें एक केयरटेकर और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर सामान खरीदे जाने का जिक्र है। एजेंसी का दावा है कि इन सामानों के बिल में उसी जमीन का पता दर्ज था। इंडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन पर कब्जे की स्थिति को अलग तरीके से दिखाने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, ये सभी अभियोजन पक्ष के आरोप हैं और इनका अंतिम निर्धारण मुकदमे की सुनवाई तथा साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगा। इस मामले में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। बाद में जून 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद मामला विशेष पीएमएलए अदालत में आगे बढ़ता रहा। सोरेन ने विशेष अदालत में आरोपों से राहत पाने के लिए डिस्टांज याचिका भी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले की जानकारी सामने आई थी। जांच एजेंसी ने बड़गाई क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़े और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की जानकारी सामने आई थी। जांच एजेंसी ने बड़गाई क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़े और जमीन के दस्तावेजों से संबंधित कई अनियमितताओं की जांच की। हाईकोर्ट के आदेश में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख था। इंडी की ओर से लगाए गए आरोपों में जमीन पर कथित कब्जे और उससे जुड़े लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर कुछ ऐसे जांच के लिए अतिरिक्त शिकायत दाखिल

कल से बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन, दिल्ली NCR में प्रदूषण पर शिकंजा कसने की तैयारी

नई दिल्ली। सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर की हवा को प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'नो पीयूसीसी, जो रहे उपायों की समीक्षा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के बिना चलने वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी उपलब्ध नहीं कराने की व्यवस्था की गई है। ईंधन केंद्रों पर वाहनों की पहचान और पीयूसीसी की स्थिति की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। CAQM की सुरक्षा ऐसे प्रवर्तन से जुड़ी समिति की 29 सितंबर को हुई बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य में संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी सर्दियों के दौरान प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें वाहन प्रदूषण के साथ-साथ सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाने और यातायात जाम वाले क्षेत्रों पर विशेष जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। पीयूसीसी व्यवस्था को लागू करने के लिए ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर ANPR कैमरों की स्थापना और उनके संचालन की समीक्षा की गई। यह तकनीक वाहन की नंबर प्लेट को पढ़कर संबंधित वाहन



के रिकॉर्ड से जानकारी मिलाने में मदद करेगी। CAQM ने पहले ही वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था के लिए Direction No. 101 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले PM2.5, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। CAQM की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली के साथ एनसीसीए के उल्लेखन पर कार्रवाई के साथ-साथ अनावश्यक जाम और उससे पैदा होने वाले अतिरिक्त वाहन उत्सर्जन को कम करना तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जून 2026 में आयोग की प्रवर्तन समिति की बैठक में भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ईंधन केंद्रों पर ANPR कैमरों की स्थापना और संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इससे स्पष्ट है कि 1 अक्टूबर की समयसीमा के लिए तकनीकी व्यवस्था पहले से तैयार की जा रही थी। प्रदूषण नियंत्रण की इस रणनीति में पुराने और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों यानी एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) वाहनों पर भी कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। ऐसे वाहनों की पहचान, जब्त और स्क्रेपिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। CAQM की पूर्व दिशा-

निर्देशों में ईंधन केंद्रों पर ANPR प्रणाली के जरिए ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था से जोड़ते हुए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख ट्रेफिक जाम वाले स्थानों की पहचान कर वहां इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ANPR आधारित स्वचालित चालान व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ अनावश्यक जाम और उससे पैदा होने वाले अतिरिक्त वाहन उत्सर्जन को कम करना तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जून 2026 में आयोग की प्रवर्तन समिति की बैठक में भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ईंधन केंद्रों पर ANPR कैमरों की स्थापना और संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इससे स्पष्ट है कि 1 अक्टूबर की समयसीमा के लिए तकनीकी व्यवस्था पहले से तैयार की जा रही थी। प्रदूषण नियंत्रण की इस रणनीति में पुराने और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों यानी एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) वाहनों पर भी कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। ऐसे वाहनों की पहचान, जब्त और स्क्रेपिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। CAQM की पूर्व दिशा-

अरब सागर में 3000 करोड़ की ड्रग्स खेप पकड़ी, पांच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। अरब सागर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 526 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले मादक पदार्थों की खेप जब्त की है। जब्त की गई खेप में हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन शामिल हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। यह कार्रवाई 25 सितंबर को लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में एक संदिग्ध ईरानी धौ को रोककर की गई। अधिकांश के दौरान नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, नाव, बरामद मादक पदार्थ और पकड़े गए लोगों को आगे की जांच तथा कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा अभियान सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। गुजरात एटीएस से मिले इनपुट के बाद संदिग्ध समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी गई। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र और हवा के माध्यम से संदिग्ध नाव की लगातार निगरानी की। उसकी गतिविधियों और मार्ग पर नजर रखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उपयुक्त समय पर कार्रवाई शुरू की और नाव का पीछा करते हुए उस रोक लिया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने नाव पर सवार बाहर तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह कार्रवाई समुद्री रास्ते से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी



नेटवर्क को रोकने के उद्देश्य से की गई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस कार्रवाई की खास अहमियत इसलिए भी है क्योंकि बरामद की गई खेप की मात्रा काफी अधिक है और इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि खेप में हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन जैसे मादक पदार्थ शामिल थे। दोनों ही पदार्थ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित और गंभीर नशीले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इतनी बड़ी खेप का समुद्री मार्ग से भारत की ओर बढ़ना सुरक्षा और मादक पदार्थ निर्यात एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जिस नाव को रोक़ा गया, वह ईरानी थी बताई गई है। उस पर पांच पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी को हिरासत में लेकर नाव को अपने निर्यात में लिया। इसके बाद नाव और उसमें मौजूद खेप को सुरक्षा घेरे में मुंबई लाया गया। अब मुंबई में केंद्रीय और राज्य की विभिन्न जांच एजेंसियां

पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जांच का उद्देश्य खेप के स्रोत, उसके संभावित प्राप्तकर्ताओं, समुद्री मार्ग और इससे जुड़े अन्य लोगों तथा संगठित नेटवर्क का पता लगाना है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ कहाँ से लाए गए थे और इन्हें भारत में किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। प्रारंभिक जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्टों में गुजरात एटीएस की पूर्व खुफिया जानकारी और मादक पदार्थ निर्यात एजेंसियों की दिशा में भी जांच का उल्लेख किया गया है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने संदिग्ध नाव की निगरानी के दौरान समुद्री और हवाई संसाधनों का इस्तेमाल किया। लगातार ट्रैकिंग के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध नाव को भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले ही रोक

लिया गया। इस तरह सुरक्षा एजेंसियों ने मादक पदार्थों की बड़ी खेप को संभावित रूप से तट तक पहुंचने से रोक दिया। इसके बाद नाव को सुरक्षा घेरे में मुंबई लाया गया, जहां मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब समुद्री रास्तों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। अरब सागर का विशाल समुद्री क्षेत्र तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका के कारण निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर समुद्री और हवाई निगरानी को एक साथ इस्तेमाल करना तस्करी रोकने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले में भी इसी तरह की समन्वित निगरानी के बाद संदिग्ध नाव तक पहुंचने में सफलता मिली। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस के बीच समन्वय को इस कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, तटरक्षक बल ने उपलब्ध खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध नाव को लगातार ट्रैक किया और उसके बाद संयुक्त अभियान के जरिए उसे रोक़ा। नाव पर सवार लोगों को हिरासत में लेने और मादक पदार्थों को जब्त करने के बाद पूरी खेप को मुंबई लाया गया है, जहां विभिन्न एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच करेगी। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस तस्करी नेटवर्क में और किसे लोग शामिल हैं।

त्योहारों पर घर जाने वालों को रेलवे की सौगात, धौलपुर-कानपुर रूट पर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढे

सूरत। त्योहारों के मौसम में घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने, राहत की बड़ी घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस से धौलपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि उधना से कानपुर सेंट्रल के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के पंचालन की अवधि बढ़ाकर 27 नवंबर 2026 तक कर दी गई है। रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने की उम्मीद है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। विशेष ट्रेनों के जरिए

भुसावल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग पर जोर

भुसावल। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने और कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति रूचि एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुसावल की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। मंडल रेल प्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भुसावल क्षेत्र के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों और राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हिंदी के प्रचार-प्रसार, कार्यालयीन कार्यों में इसके प्रभावी इस्तेमाल, कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं के आयोजन तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री के हिंदी दिवस संदेश के वाचन के साथ हुई। इसके बाद समिति की विभिन्न गतिविधियों और सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उपयोग को और बढ़ाने तथा कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। बैठक में यह बात सामने आई कि राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन केवल औपचारिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर दैनिक कार्यालयीन कामकाज का हिस्सा बनना चाहिए। बैठक के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ई-पत्रिका ‘भुसावल दर्पण’ का विमोचन भी किया गया। समिति के अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल ने ई-पत्रिका का

बंगाल में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया: मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर लोकतंत्र के सवाल उठ रहे हैं

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, मतदान का अधिकार पवित्र माना जाता है। क्योंकि यह लोकतंत्र की सच्ची नींव है। कोई अन्य शासन प्रणाली अपने नागरिकों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार नहीं देती है। यह अधिकार केवल लोकतंत्र में ही पाया जाता है। और यदि कोई नागरिक अपने मतदान के सच्चे अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता, तो यह एक बड़ा पाप है। इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि न्यायाधिकरण द्वारा 93 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सही साबित हुए हैं। फिर भी वे पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर सके। क्या यह लोकतंत्र का अपमान या उल्लंघन नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार

गुजरात रेंट बिल के विरोध में सूरत के वकीलों ने चार दिन कोर्ट से बनाई दूरी, न्यायिक व्यवस्था बदलने पर जताई आपत्ति

सूरत। गुजरात रेंट बिल-2026 को लेकर राज्यभर में अधिवक्ताओं का विरोध तेज होता जा रहा है। प्रस्तावित कानून में किराया संबंधी विवादों के निपटारे की व्यवस्था में किए गए बदलावों को लेकर वकली संगठनों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इसी क्रम में सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी बिल के विरोध में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नियमित न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन की काउंसिल बैठक में बिल के विभिन्न प्रावधानों, प्रस्तावित नई व्यवस्था और उससे न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने अपने फैसले की जानकारी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सहित अधीनस्थ अदालतों को भी दे दी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रस्तावित रेंट कानून में किराया विवादों की सुनवाई और उनके निपटारे के लिए मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। वकीलों की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि किराया विवादों को पारंपरिक अदालतों



विमोचन किया। ‘भुसावल दर्पण’ में समिति से जुड़े सदस्य कार्यालयों की राजभाषा गतिविधियों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा पत्रिका में रचनात्मक, साहित्यिक और अन्य उपयोगी सामग्री भी शामिल की गई है। ई-पत्रिका के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ‘भुसावल दर्पण’ के विमोचन को बैठक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पत्रिकाएं कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को भी सामने लाने का माध्यम बन सकती हैं। विभिन्न सदस्य कार्यालयों की गतिविधियों को एक मंच पर प्रस्तुत करने से एक-दूसरे के कार्यों से सीखने और राजभाषा संबंधी अच्छी पहलों को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। बैठक में कर्मचारियों को हिंदी के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए विभिन्न



विकल्प मिलेगा।

इसी तरह बांद्रा टर्मिनस और धौलपुर के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09023/09024 के दो फेरे होंगे। ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस से 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर धौलपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09024 धौलपुर से 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4 बजकर 10 मिनट पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन से मुंबई

विशेष प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के माध्यम से विद्यालय में राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यों और गतिविधियों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्तर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से कर्मचारियों को हिंदी के उपयोग पर भी जोर दिया गया, ताकि कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में हिंदी से प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक जानकारी मिल सके।

बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ‘हिंदी मित्र’ कर्मचारियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। अधिकारियों का मानना था कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को पहचान और प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। ऐसे सम्मान से अन्य कर्मचारियों को भी कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने सुझाव और विचार भी समिति के समक्ष रखे। इस अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से दृश्य-श्रव्य माध्यम से के प्रति रूचि बढ़ाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में हिंदी का उपयोग के लिए व्यावहारिक जानकारी मिल सके। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ‘हिंदी मित्र’ कर्मचारियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। अधिकारियों का मानना था कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को पहचान और प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। ऐसे सम्मान से अन्य कर्मचारियों को भी कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने सुझाव और विचार भी समिति के समक्ष रखे। इस अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से दृश्य-श्रव्य माध्यम से

महंगे कोयले के बीच उद्योगों को ऊर्जा बचत का मंत्र, सूरत में बॉयलर ऑपरेटरों की चार दिवसीय ट्रेनिंग

सूरत। कोयले की बढ़ती कीमतों और औद्योगिक उत्पादन लागत में लगातार हो रही वृद्धि के बीच ऊर्जा दक्षता बढ़ाना उद्योगों के लिए अहम चुनौती बन गया है। खासकर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और अन्य ऊर्जा-आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए और थर्मोपैक के संचालन को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य से सूरत में बॉयलर ऑपरेटरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय स्टीम सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन (एसएसओ) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योगों को कम ईंधन में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने, अनावश्यक गर्मी और ऊर्जा नुकसान को कम करने तथा बॉयलर की कार्यक्षमता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताए जा रहे हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माफ़्नो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद की ओर से केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के EEnergy Efficiency Improvement of



खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। एसोसिएशन ने विशेष रूप से एकरफा आदेश, मुकदमा खारिज करने, वारंट जारी करने या समन जैसी कार्रवाई से बचने का अनुरोध किया है। वकीलों का कहना है कि विरोध के कारण कुछ मामलों में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की अदालत में उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस संबंध में अदालतों को पूर्व सूचना देने का उद्देश्य यही बताया गया है कि विरोध की अवधि में पक्षकारों के अधिकार प्रभावित न हों और बाद में उन्हें अनावश्यक कानूनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

विशेष प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के माध्यम से विद्यालय में राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यों और गतिविधियों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्तर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को पहचान और प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। ऐसे सम्मान से अन्य कर्मचारियों को भी कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने सुझाव और विचार भी समिति के समक्ष रखे। इस अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से दृश्य-श्रव्य माध्यम से के प्रति रूचि बढ़ाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में हिंदी का उपयोग के लिए व्यावहारिक जानकारी मिल सके। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ‘हिंदी मित्र’ कर्मचारियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। अधिकारियों का मानना था कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को पहचान और प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। ऐसे सम्मान से अन्य कर्मचारियों को भी कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने सुझाव और विचार भी समिति के समक्ष रखे। इस अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से दृश्य-श्रव्य माध्यम से



Boilers (ईईआईबी) प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को GEF-7 का सहयोग प्राप्त है। सूरत करने, अनावश्यक गर्मी और ऊर्जा नुकसान को कम करने तथा बॉयलर की कार्यक्षमता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माफ़्नो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद की ओर से केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के EEnergy Efficiency Improvement of

अपनी निर्धारित तारीखों पर अदालत पहुंच गए। बाद में जब उन्हें अधिवक्ताओं ने कार्य से दूर रहने के निर्णय की जानकारी मिली तो कई पक्षकारों को वापस लौटना पड़ा। जिन लोगों ने पहले से अपने मामलों की सुनवाई के लिए अदालत आने की तैयारी की थी, उनके लिए अचानक सामने आई स्थिति परेशानी का कारण बनी। एडवोकेट भावेशभाई रवारी के मुताबिक विरोध संबंधी प्रस्ताव सुबह करीब 11 बजे सामने आया था। इसके चलते कई पक्षकारों और क्लार्कट्स को समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि अब बार एसोसिएशन की ओर से पक्षकारों को विरोध की अवधि और फैसले की जानकारी दी जा रही है, ताकि जिन मामलों में तत्काल व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, उनमें लोगों को अनावश्यक रूप से अदालत परिसर तक आने की परेशानी न उठानी पड़े। गुजरात रेंट बिल को लेकर केवल सूरत में ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी अधिवक्ताओं की ओर से आपत्तियां सामने आई हैं। अहमदाबाद सहित विभिन्न शहरों के बार एसोसिएशनों ने प्रस्तावित

सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04167 कानपुर सेंट्रल से 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 9 बजकर 40 मिनट पर उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन से गुजरात में रहने वाले यात्रियों को उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध होगा। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में आरक्षण की मांग बढ़ने के कारण विशेष ट्रेनों का संचालन रेलवे की वार्षिक यात्री प्रबंधन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के आसपास गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच यात्रियों की आवाजाही बढ़ती है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार और कारोबार के सिलसिले में गुजरात तथा महाराष्ट्र के शहरों में रहते हैं और त्योहारों पर अपने घरों की ओर लौटते हैं। ऐसे में लंबी दूरी के मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाने से यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। रेलवे ने दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के पंचालन में भी विस्तार किया है। ट्रेन संख्या 09049/09050

सूरत में शराबियों द्वारा की गई बदसलूकी से आक्रोशित भाजपा महिला पार्षद ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। ऐसा लगता है मानो गुजरात मॉडल अब शराब का मॉडल बन गया है। प्रतिदिन लाखों रुपये की शराब जन्त की जाती है और उससे कहीं अधिक खपत होती है। फिर भी शर्मिंदा होने के बजाय, गृह मंत्री के गृह नगर के उपमुख्यमंत्री हर्ष संधवी सूरत में ही शराबियों के जमावड़े से तंग आ चुके हैं। वहीं, भाजपा की वार्ड 16 से महिला पार्षद संगीताबेन परमार ने स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त और स्थायी समिति के अध्यक्ष से गुस्से में कहा कि पुणे के धनवर्षा वाई कार्यालय के पास शराबी और असामाजिक तत्व मंडराते रहते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए वहां जाना खतरनाक हो गया है। इस तरह की प्रस्तुति से भारी आक्रोश फैल गया, साथ ही उपस्थित दोनों गणन्याय व्यक्तियों के सामने इन असामाजिक तत्वों की तस्वीरें रखकर और पूरे वार्ड कार्यालय को दूसरी शिफ्ट में स्थानांतरित करने की बात कहकर हंगामा मचा दिया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि लैपटॉप-कंप्यूटर चोरी हो जाने पर शिकायत कौन करे जब एसएमसी प्रशासन गहरी नींद में सो रहा हो? अब धनवर्षा वाई कार्यालय के संबंध में दी गई प्रस्तुति के बाद प्रशासन जाग उठा है और अपने काम में सक्रिय हो गया है। यह शिकायत का निश्चित रूप से दर्शाती है कि अब शहर में पुलिस की ओर से कोई पुकार या धमकी



नहीं चलती। क्योंकि सूरत में ही, जब पीएसआई, पीआई से लेकर सूरत नगर निगम के कुछ अधिकारियों तक, पुलिस प्रशासक तीन साल से अधिक समय से गृह मंत्री के घर से चिपके हुए हैं, तो अवैध शराब के तस्करों से संबंध कैसे न बने? इतना ही नहीं, दुम्मास, वेसु, सिटीलाइट जैसे पॉश इलाकों में, जिन्हें हाई-फाई एरिया कहा जाता है और जहां से गृह मंत्री चुने गए हैं, महंगी विदेशी शराब की बोतलों की होम डिलीवरी का जा रही है। और जब न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा सूरत इससे वाकिफ है, तो आप, गृह मंत्री जी, कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं? फिर ये महंगी विदेशी शराब की बोतलें सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं हैं, बल्कि उच्च वर्ग की महिलाएं, जो पुरुषों के बराबर हो रही

लिया है। भारतीय रेल ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की मंजूरी दी है। अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद प्रकाश के अनुसार, प्रस्तावित नई रेल सेवा लगभग 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई महत्वपूर्ण स्थानों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। भुज-बरौनी के बीच प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस गुजरात और उत्तर भारत के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक और विकल्प उपलब्ध करएगी। इस रेल सेवा से गुजरात में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को नियंत्रित यात्रियों के लिए भी यह सेवा उपयोगी होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस श्रृंखला के विस्तार को रेलवे की लंबी दूरी की यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। त्योहारों के दौरान रेलवे के सामने सबसे

सूरत में शराबियों द्वारा की गई बदसलूकी से आक्रोशित भाजपा महिला पार्षद ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की

नहीं होता। लेकिन सभी प्रकार की सेवाओं की ये सारी सुविधाएँ सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही उपलब्ध हैं। और मंत्री से लेकर पहरेदार और शराब तस्कर तक, हर कोई पुलिस की कृपा का फायदा उठा रहा है। अब बात करते हैं असली ब्रांड की शराब के नाम पर नकली शराब की बिक्री की। जिस तरह मुनाफाखोर लोग धी, दूध, पनीर, मावा, तेल आदि खाद्य पदार्थों को भारी मुनाफे पर बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी तरह अवैध शराब बेचने वाले भी शराब की बोतलों को असली ब्रांड की शराब के नाम पर ऊँची कीमतों पर बेचकर शराबियों के ज़िगर को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उन्हे मोत के मुँह में धकेल रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि गुजरात अब मिनी दमन और मिनी मुंबई बनता जा रहा है। अंत में, एक बात और, गुजरात के महशूर गृह मंत्री के शासनकाल में लता कोर्ड में बड़ी संख्या में शराब के आदी लोगों की मौत के बाद पूरे गुजरात में मचे बवाल के बावजूद गृह मंत्री का इस पर कोई असर नहीं हुआ। गृह मंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? आज जब शराब के दानव का चंगुल सूरू गांवों से लेकर गुजरात के सहानगरों के होटलों और आलीशान आवासों तक फैल चुका है, तो जनता के पास एकमात्र विकल्प यही बचा है कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें और अपनी फिलतला साबित करें।

सूरत में बॉयलर ऑपरेटरों की चार दिवसीय ट्रेनिंग

में विशेष रूप से बॉयलर और थर्मोपैक के वैज्ञानिक और व्यवस्थित इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रतिभागियों को समझा रहे हैं कि बॉयलर में ईंधन की गुणवत्ता, कंभेशन की स्थिति, हवा और ईंधन के अनुपात, संचालन के विभिन्न मानकों तथा उपकरणों के रखरखाव का उच्च दक्षता पर सीधा असर पड़ता है। यदि इन पहलुओं को नियमित निगरानी की जाए और संचालन में जरूरी सुधार किए जाएं तो ईंधन की खपत को नियंत्रित करते हुए बॉयलर से बेहतर प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण विशेषज्ञ डॉ. सोमचाई डेहापनिमकुल को विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके पास अमेरिका की आयोवा यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री है। ऊर्जा प्रबंधन, बॉयलर और स्टीम सिस्टम के क्षेत्र में उनका अंतराष्ट्रीय अनुभव रहा है। वे थाईलैंड के एनजी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से संबंधित तकनीकी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर

चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान वे प्रतिभागियों को बॉयलर संचालन और स्टीम सिस्टम की दक्षता से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। चार दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान बॉयलर ऑपरेटरों को ऐसी व्यावहारिक समझ प्रदान करना है, जिसका इस्तेमाल वे अपनी-अपनी औद्योगिक इकाइयों में प्रतिदिन नुकसान न हों। कई बार बॉयलर संचालन में छोटी-छोटी तकनीकी कमियों के कारण अतिरिक्त ईंधन खर्च होता है। कंभेशन की सही निगरानी, बॉयलर की नियमित जांच, हीट लॉस को नियंत्रित करना और स्टीम सिस्टम को उचित तरीके से संचालित करना ऐसे उपाय हैं, जिनसे ऊर्जा दक्षता में सुधार बढ़ती और चौथे दिन प्रतिभागियों को

सूरत के वकीलों ने चार दिन कोर्ट से बनाई दूरी, न्यायिक व्यवस्था बदलने पर जताई आपत्ति

अपनी निर्धारित तारीखों पर अदालत पहुंच गए। बाद में जब उन्हें अधिवक्ताओं ने कार्य से दूर रहने के निर्णय की जानकारी मिली तो कई पक्षकारों को वापस लौटना पड़ा। जिन लोगों ने पहले से अपने मामलों की सुनवाई के लिए अदालत आने की तैयारी की थी, उनके लिए अचानक सामने आई स्थिति परेशानी का कारण बनी। एडवोकेट भावेशभाई रवारी के मुताबिक विरोध संबंधी प्रस्ताव सुबह करीब 11 बजे सामने आया था। इसके चलते कई पक्षकारों और क्लार्कट्स को समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि अब बार एसोसिएशन की ओर से पक्षकारों को विरोध की अवधि और फैसले की जानकारी दी जा रही है, ताकि जिन मामलों में तत्काल व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, उनमें लोगों को अनावश्यक रूप से अदालत परिसर तक आने की परेशानी न उठानी पड़े। गुजरात रेंट बिल को लेकर केवल सूरत में ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी अधिवक्ताओं की ओर से आपत्तियां सामने आई हैं। अहमदाबाद सहित विभिन्न शहरों के बार एसोसिएशनों ने प्रस्तावित

के साथ व्यापक चर्चा की जाए। उनका कहना है कि कानून बनाने से पहले उसके व्यावहारिक प्रभावों, न्यायिक प्रक्रिया, पक्षकारों के अधिकार और कानूनी पेशे से जुड़े पहलुओं पर विचार होना जरूरी है। दूसरी ओर, प्रस्तावित रेंट व्यवस्था के संबंध में अंतिम स्वरूप और उसके लागू होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वर्तमान में बिल को लेकर सामने आ रही आपत्तियों के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा जारी है। सूरत में चार दिन तक कोर्ट कार्यवाही से दूर रहने के निर्णय ने इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर भी प्रमुख बना दिया है। आने वाले दिनों में बार एसोसिएशन और सरकार के बीच बातचीत तथा बिल के प्रावधानों पर होने वाली चर्चा से स्थिति की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल अधिवक्ताओं का विरोध किराया विवादों की नई व्यवस्था, न्यायिक संस्थाओं की भूमिका, प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार और कानूनी पेशे पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। सूरत के साथ गुजरात के अन्य शहरों में भी इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है।

दिवाली-छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेल ने घोषित की 162 अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं

सूरत। दिवाली और छठ पर्व के दौरान मुंबई, पुणे और उत्तर भारत के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य रेल ने अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का बड़ा परिचालन कार्यक्रम घोषित किया है। पर्वों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए मध्य रेल विभिन्न प्रमुख मार्गों पर 162 अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं चलाएगी। इन नई सेवाओं के जुड़ने के बाद अब तक घोषित पर्व विशेष ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 580 हो गई है। नई ट्रेनों के जरिए मुंबई और पुणे से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर और पूर्वी भारत के कई प्रमुख शहरों के लिए यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे। रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के दौरान अपने घर लौटने वाले कामगारों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

दिवाली और छठ के अवसर पर हर वर्ष मुंबई और पुणे से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ने के कारण निमित्त सेवाओं में आरक्षण जल्दी भर जाता है। इसे देखते हुए मध्य रेल ने अलग-अलग गंतव्यों के लिए अतिरिक्त सेवाओं की योजना बनाई है। इनमें एसी, सुपरफास्ट और अन्य विशेष ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों

स्वच्छता ही सेवा अभियान में सोलापुर रेल मंडल ने दिखाई जनभागीदारी, सफाई से लेकर विरासत संरक्षण तक कई पहल

सोलापुर। स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित रखने के बजाय पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन, विरासत स्थलों की देखभाल और सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जोड़ते हुए, केंद्रीय रेलवे के सोलापुर मंडल में ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान के तहत व्यापक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंडल के विभिन्न स्टेशनों, ट्रेनों, रेलवे कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों में चलाए जा रहे अभियान में रेलवे कर्मचारियों के साथ यात्रियों, विद्यार्थियों, बच्चों और कॉलोनीवासियों ने भी भागीदारी की। अभियान के दौरान जहां स्टेशनों और ट्रेनों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, वहीं सूखे और गीले कचरे को अलग करने, घरेलू स्तर पर खाद बनाने, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने तथा सफाई मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया।

स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए केंद्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन की सोलापुर इकाई ने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए ‘साफ और सुंदर गार्डन’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।

प्रतियोगिता में 83 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से स्वच्छता, हरियाली, सुंदर वातावरण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें अपने दायित्व के वातावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित करना रहा।

अभियान के तहत सोलापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सफाई गतिविधियों को व्यापक रूप दिया गया। सोलापुर, कलवुर्गी, वाडी, अक्कलकोट और पकनी सहित विभिन्न स्टेशनों पर विशेष सफाई अभियान चलाए गए। ‘प्लेटफॉर्म, पर्सर और यात्रियों की आवाजाही वाले स्थानों की सफाई के साथ-साथ कचरे के उचित निस्तारण पर ध्यान दिया गया। रेलवे की से सुखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ

की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे मार्गों पर सेवाएं बढ़ाई हैं, जहां त्योहारों के दौरान यात्रियों का दबाव अधिक रहता है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर के बीच 12 साप्ताहिक एसी विशेष सेवाएं संचालित की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01043 प्रत्येक मंगलवार को 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 11.45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01044 प्रत्येक गुरुवार को 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक समस्तीपुर से सुबह 3 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। इस सेवा से मुंबई और बिहार के बीच त्योहार के समय अतिरिक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

समस्तीपुर जाने वाली इन विशेष ट्रेनों को रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इनमें ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इंदरसी, पिंपरी, नरसिंहपुर, मदन जंक्शन, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिक्की, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इससे केवल मुंबई और समस्तीपुर के यात्रियों को ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले कई शहरों के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।

बिहार के यात्रियों के लिए एक अन्य



महत्वपूर्ण सेवा लोकमान्य तिलक टर्मिनस और दानापुर के बीच शुरू की जा रही है। इस मार्ग पर 88 दैनिक विशेष सेवाएं संचालित होंगी। ट्रेन संख्या 01143 नौ अक्टूबर से 21 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होकर अगले दिन रात 9.50 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01144 दस अक्टूबर से 22 नवंबर तक प्रतिदिन रात 12.10 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। दैनिक सेवा होने के कारण उन यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें त्योहारों

के दौरान अपनी यात्रा की तारीख में अधिक लचीलापन चाहिए। दानापुर विशेष ट्रेन को ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिका, भुसावल, इंदरसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिक्की, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इस मार्ग के जरिए मुंबई क्षेत्र से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और संतरागाछी के बीच आठ साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन सेवाएं भी संचालित

की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01107 छह से 27 अक्टूबर तक प्रत्येक मंगलवार को रात 8.20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5 बजे संतरागाछी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01108 आठ से 29 अक्टूबर तक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे संतरागाछी से रवाना होकर अगले दिन रात 9.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। संतरागाछी जाने वाली ट्रेन को नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इससे

सूरत टेक्सटाइल मार्केट में पल्लेदारों की मजदूरी बढ़ी, 10 रुपये प्रति पार्सल पर बनी सहमति

सूरत। शहर के टेक्सटाइल मार्केटों में पार्सल उठाने वाले पल्लेदारों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद आखिरकार बातचीत के जरिए सुलझ गया। मजदूर संगठनों और मार्केट प्रबंधन के बीच हुई चर्चा के बाद प्रति पार्सल लेबर रेट में 10 रुपये की बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। मजदूर संगठनों ने पहले प्रति पार्सल 20 रुपये मजदूरी बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन वार्ता के बाद दोनों पक्ष 10 रुपये की वृद्धि प्रति पार्सल पर सहमत हुए। समझौता होने के बाद रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट और मिलेनियम मार्केट में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर चल रही हड़ताल समाप्त कर दी गई और पार्सल उठाने का काम दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो गया।

टेक्सटाइल कारोबार में पार्सल की आवाजाही का काम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में कपड़े के पार्सल भेजने और मंगाने के दौरान मार्केटों में बड़ी संख्या में पल्लेदार सामान को दुकानों, गोदामों और वाहनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में मजदूरी को लेकर विवाद खड़ा होने से मार्केट की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। हड़ताल के कारण कुछ समय के लिए पार्सल उठाने और माल की आवाजाही प्रभावित हुई, जिसके बाद मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल की गई।

मजदूर संगठनों की ओर से पिछले कई वर्षों से लेबर रेट में संशोधन की मांग की जा रही थी। संगठन का कहना था कि महंगाई, परिवहन लागत और रोजमर्रा के खर्च में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि पार्सल उठाने वाले मजदूरों की मजदूरी में पिछले सात-आठ वर्षों के दौरान कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी को आधार बनाकर मजदूर संगठनों ने मार्केट प्रबंधन के सामने प्रति पार्सल मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।

महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बनारस के बीच 14 साप्ताहिक विशेष सेवाएं भी घोषित की गई हैं। ट्रेन संख्या 05168 प्रत्येक रविवार को 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक शाम 6.10 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और तीसरे दिन रात 12.50 बजे बनारस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05167 प्रत्येक शनिवार को 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सुबह 9.50 बजे बनारस से रवाना होकर अगले दिन शाम 4.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

बनारस जाने वाली विशेष ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इंदरसी, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर और तीसरे दिन रात 12.50 बजे बनारस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05167 प्रत्येक शनिवार को 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सुबह 9.50 बजे बनारस से रवाना होकर अगले दिन शाम 4.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी मध्य रेल ने विशेष व्यवस्था की है। खड़की और हजरत निजामुद्दीन के बीच 28 द्वि-साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन संख्या 01483 छह अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5.30



इस मांग को लेकर सूरत के रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट और मिलेनियम मार्केट में पार्सल उठाने वाले कुलियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल के चलते मार्केट में पार्सल की आवाजाही पर असर पड़ने लगा। इसके बाद मजदूर प्रतिनिधियों और मार्केट प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी मांग और व्यावहारिक परिस्थितियों को समाने रखा। चर्चा के बाद मार्केट एसोसिएशन की ओर से प्रति पार्सल लेबर रेट में 10 रुपये की बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई गई।

सूरत डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रॉसपोर्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा और प्रवक्ता शान खान ने बताया कि मजदूर संगठनों की ओर से लेबर रेट में संशोधन को लेकर पहले ही मार्केट प्रबंधन को पत्र भेजा गया था। उनका कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में ईंधन की कीमतों और महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के घरेलू खर्च में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में पार्सल उठाने वाले श्रमिकों की मजदूरी में समय के अनुरूप बदलाव जरूरी हो गया था।

यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार, टेक्सटाइल मार्केट में पार्सल उठाने का काम करने वाले पल्लेदारों की मजदूरी

बजे खड़की से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6.10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01484 सात अक्टूबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रात 10.10 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होकर अगले दिन रात 10.15 बजे खड़की पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर और मथुरा जंक्शन पर होगा। इसके चलते महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के बीच त्योहार के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए खड़की और सांगानेर के बीच 12 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष सेवाएं संचालित की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01411 प्रत्येक गुरुवार को 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक सुबह 9.45 बजे खड़की से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.45 बजे सांगानेर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01412 प्रत्येक शुक्रवार को 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक सुबह 11.35 बजे सांगानेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे खड़की पहुंचेगी।

सांगानेर जाने वाली विशेष ट्रेन का ठहराव लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, कोटा और सवाई माधोपुर में होगा। इससे महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच त्योहारों के दौरान

अतिरिक्त रेल संपर्क मजबूत होगा।

मध्य रेल की ओर से अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का यह विस्तार ऐसे समय किया गया है जब दिवाली के साथ छठ पर्व के कारण उत्तर भारत की ओर यात्रियों की आवाजाही में तेजी आने की संभावना है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पूर्वी भारत के बड़ी संख्या में लोग रेलगाड़ी और कारोबार के सिलसिले में रहते हैं। पर्व के अवसर पर इनमें से बड़ी संख्या में यात्री अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं। ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों से नियमित सेवाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। रेलवे को देखते हुए समय से अपील की जाती है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय, तारीख, ठहराव और आरक्षण की स्थिति को पुष्टि कर लें। विशेष ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी हो सकता है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए समय से टिकट आरक्षित कराने और स्टेशन पर पर्याप्त समय पहले पहुंचने से यात्रा को अधिक सुगम बनाया जा सकता है। मध्य रेल द्वारा घोषित 162 अतिरिक्त सेवाओं के साथ अब पर्व के लिए घोषित विशेष ट्रेनों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जिससे इस बार दिवाली और छठ के दौरान मुंबई तथा उत्तर और पूर्वी भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है।



पर्याप्त संख्या में डस्टबिन उपलब्ध कराने और सफाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुरक्षा सामग्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

ट्रेनों की स्वच्छता को लेकर भी विशेष अभियान चलाया गया। लातूर और पंढरपुर में चर्चनित ट्रेनों की सफाई की गई और कोचों के साथ शौचालयों की स्थिति की जांच की गई। इसके अलावा लिनन, पेंटी कार तथा ट्रेन में उपलब्ध सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। रेलवे का प्रयास रहा कि यात्रियों को सफर के दौरान स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करने के साथ ट्रेन के विभिन्न हिस्सों की नियमित सफाई और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाए। अभियान के दौरान यात्रियों से भी अपील की गई कि वे कचरा इधर-उधर न फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का इस्तेमाल करें। सोलापुर मंडल ने कचरा प्रबंधन को अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। रेलवे कॉलोनियों और कार्यालयों में चार प्रकार के कचरे को अलग-अलग करने और उसके उचित निस्तारण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि घर और कार्यालय से निकलने वाले अलग-अलग प्रकार के कचरे को एक साथ मिलाने के बजाय शुरुआत से ही अलग रखा जाए, ताकि उसके पुनर्चक्रण को संदेश दिया गया। खेल मैदान और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई रखने तथा खेल आयोजनों के दौरान उत्पन्न कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के सोलापुर, वाडी, कलवुर्गी और पंढरपुर में आयोजित जनभागीदारी कार्यक्रमों में ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा पृथक्करण

और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर विशेष जोर दिया गया। लोगों को कपड़े के थैलों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलापुर और वाडी रेलवे स्टेशनों पर कपड़े के थैले वितरित किए गए। इस पहल के जरिए प्लास्टिक की थैलियों पर निर्भरा कम करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

स्वच्छता अभियान को रेलवे की विरासत से भी जोड़ा गया। पंढरपुर रेलवे स्टेशन, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तथा सोलापुर रेलवे स्टेशन के विरासत स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इन स्थानों की सफाई के माध्यम से रेलवे की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उनके प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। अभियान का उद्देश्य यह भी रहा कि रेलवे की पुरानी इमारतों, संरचनाओं और विरासत से जुड़े स्थलों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखा जाए, ताकि उनकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रह सके। सोलापुर रेलवे खेल मैदान में क्रिकेट और वॉलीबॉल मैचों का आयोजन भी अभियान का हिस्सा रहा। खेल गतिविधियों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के बीच टीम भावना और स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वच्छता एवं जिम्मेदार कचरा प्रबंधन का संदेश दिया गया। खेल मैदान और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई रखने तथा खेल आयोजनों के दौरान उत्पन्न कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के प्रति भी जागरूकता पैदा की गई। अभियान में रचनात्मकता और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘कबाड़

से जुगाड़’ पहल भी आयोजित की गई। इसके तहत रेलवे के कबाड़ से भाप इंजन का एक मॉडल तैयार किया गया। एसपीएआरएमपी, सोलापुर की टीम द्वारा हाथ से तैयार किए गए इस मॉडल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अनुपयोगी समझी जाने वाली वस्तुओं का रचनात्मक तरीके से पुनः उपयोग किया जा सकता है। भाप इंजन के मॉडल ने कबाड़ के पुनर्चक्रण, रचनात्मक सोच और रेलवे की विरासत को एक साथ जोड़ने का काम किया। स्वच्छता अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष सफाई मित्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा रहा। मंडल रेलवे अस्पताल, सोलापुर और वाडी स्वास्थ्य केंद्र में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में सफाई कार्य से जुड़े कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। सफाई मित्रों को मास्क, दस्ताने और हाथ साफ करने का द्रव भी वितरित किया गया, ताकि सफाई कार्य के दौरान स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम किया जा सके। सोलापुर के न्यू कॉर्रिज परिसर में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब 50 रेलवे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच के साथ कर्मचारियों ने स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और कार्यस्थल आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई रखने का प्रभावी बाने के लिए सफाई कर्मियों का सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसी सोच के तहत अभियान में सफाई मित्रों के कल्याण को भी प्रमुखता दी गई।

‘हनुमान अंश’ से विद्यार्थियों ने जाना सनातन संस्कृति और सेवा का संदेश

सूरत। विद्यार्थियों को पुस्तकीय शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन के प्रेरक आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी नगर, बमरोली रोड, पांडेसरा स्थित श्री कृष्णराज विद्यालय की ओर से विशेष शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 29 सितंबर 2026 को मिराज सिनेमा में सनातन संस्कृति पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म ‘हनुमान अंश’ के विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था की। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ फिल्म देखी और भगवान हनुमान के चरित्र से जुड़े साहस, समर्पण, भक्ति, सेवा और कर्तव्य जैसे जीवन मूल्यों को समझने का अवसर प्राप्त किया।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराने के



साथ उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करना था। आधुनिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों से जोड़ना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत फिल्म प्रदर्शन को केवल मनोरंजन का माध्यम न बनाकर शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। फिल्म देखने

के लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रियायती शुल्क निर्धारित किया गया था। मात्र 92 रुपये के शुल्क में विद्यार्थियों को फिल्म देखने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।

इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। विद्यालय की ओर से पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया, ताकि विद्यार्थियों को सिनेमा तक पहुंचने, फिल्म देखने और वापस लौटने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

‘हनुमान अंश’ को सनातन संस्कृति और भगवान हनुमान के प्रेरक चरित्र से जोड़कर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया।

फिल्म के माध्यम से बच्चों और किशोर विद्यार्थियों को भगवान हनुमान के जीवन से जुड़े विभिन्न आदर्शों को समझने का अवसर मिला। विशेष रूप से बल के साथ बुद्धि, शक्ति के साथ विनम्रता, भक्ति के साथ कर्तव्य और सामर्थ्य के साथ सेवा भावना को महत्व देने वाले संदेश विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहे। फिल्म के प्रसंगों ने विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर दिया कि भारतीय परंपरा में चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों को कितना महत्व दिया गया है।

विद्यालय के ट्रस्टी एवं प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जिसमें ज्ञान के साथ संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सेवा भावना भी विकसित हो। उन्होंने कहा

कि भारतीय संस्कृति में भगवान हनुमान का चरित्र साहस, समर्पण, निष्ठा और सेवा का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। ऐसे प्रेरक प्रसंग विद्यार्थियों को अपने जीवन में सकारात्मक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थी शिक्षा और तकनीक के विभिन्न माध्यमों से लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वापसी सांस्कृतिक विरासत और नैतिक परंपराओं की जानकारी भी दी जाए। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी जड़ों को समझने और समाज तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने का प्रयास किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से विद्यालय की ओर से समय-समय पर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

सूरत से उदयपुर तक दौड़ेगी वंदे भारत, गुजरात राजस्थान के बीच तेज होगा रेल संपर्क

सूरत। गुजरात और राजस्थान के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। पश्चिम रेलवे की ओर से सूरत और उदयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से लैस इस सेमी हाई-स्पीड ट्रेन के शुरू होने से दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय कम होने के साथ कारोबार, पर्यटन और अन्य जरूरी यात्राओं के लिए भी कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने का उम्मीद है। ट्रेन सेवा सूरत से 4 अक्टूबर और उदयपुर से 3 अक्टूबर से शुरू होगी। सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस ट्रेन से गुजरात के दक्षिणी हिस्से को राजस्थान में उदयपुर और मार्ग में आने वाले कई शहरों से सीधा रेल संपर्क मिलेगा।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या

26903 सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सूरत से सुरुआत होगी। यह ट्रेन सूरत से सुबह 6.10 बजे रवाना होकर दोपहर 1.40 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को सुबह सूरत से रवाना होकर दोपहर तक उदयपुर पहुंचने की सुविधा मिलेगी। वहीं वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 26904 उदयपुर-सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस 3 अक्टूबर से निर्धारित छह दिनों में चलेगी। यह ट्रेन उदयपुर से दोपहर 3.35 बजे रवाना होकर रात 11 बजे सूरत पहुंचेगी। इस नई सेवा को गुजरात और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूरत देश के प्रमुख औद्योगिक और कारोबारी केंद्रों में शामिल है, जबकि उदयपुर राजस्थान का

प्रमुख पर्यटन एवं व्यापारिक शहर है। दोनों शहरों के बीच बड़ी संख्या में लोग व्यापार, रोजगार, पर्यटन और निजी कार्यों के लिए आवागमन करते हैं। ऐसे में तेज और आधुनिक रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों को सड़क या अन्य साधनों के मुकाबले एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा। सूरत से उदयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेन भरुक, वडोदरा, आणंद, मणिगनगर, अमरवा, हिम्मतनगर, शालाजी रोड, डूंगरपुर और जावर स्टेशनों पर रुकेगी। इन उद्देश्यों के कारण केवल सूरत और उदयपुर के यात्रियों की ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि मार्ग में आने वाले गुजरात और राजस्थान के शहरों के यात्रियों को भी तेज रेल सेवा का फायदा मिल सकेगा।